राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 376/2023

धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री शांतिलाल जैन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- पुलिस चौकी के पास, पुरानी तहसील के पीछे, हुरड़ा, जिला. भीलवाड़ा (राजस्थान)----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. पुलिस अधीक्षक, जिला-उदयपुर, राजस्थान।

3. स्टेशन हाउस ऑफिसर (एस.एच.ओ), पुलिस स्टेशन-हिरन मगरी, जिला-उदयपुर (राज)।

4. भगवती लाल डाक पुत्र भंवर लाल जैन, निवासी- 1आर-1, गायत्री नगर, डुंगला हाउस, वार्ड संख्या 9, हिरण मागरी, सेक्टर-5, उदयपुर, राज।

5. योगीश डाक पुत्र भगवती लाल डाक, निवासी- 1आर-1, गायत्री नगर, डुंगला हाउस, वार्ड संख्या 9, हिरन मगरी, सेक्टर-5, उदयपुर, राज।

6. प्रिंस डाक पुत्र भगवती लाल डाक, निवासी- 1आर-1, गायत्री नगर, डुंगला हाउस, वार्ड संख्या 9, हिरन मगरी, सेक्टर-5, उदयपुर, राज।

7. धनश्री डाक पत्नी भगवती लाल डाक, निवासी- 1आर-1, गायत्री नगर, डुंगला हाउस, वार्ड नंबर 9, हिरण मगरी, सेक्टर-5, उदयपुर, राज---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री राजेश पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ
सहायक श्री आयुष गहलोत।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री एम. ए. सिद्दीकी, जी. ए. सह ए. ए. जी. के साथ सहायक श्री रोहित मुथा ।

श्री धीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ
सहायक सुश्री प्रियंका बोराना।

माननीय न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

रिपोर्टेबल 12/02/2024

डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जेः-

1. यह वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका एक नाबालिग बेटे की अभिरक्षा का दावा करने के लिए पेश की गई है। हालाँकि, याचिकाकर्ता का विद्वान वकील वर्तमान याचिका की स्थिरता के रूप में उसकी प्रार्थना को प्रतिबंधित करता है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता और बेटी (उत्तरदाता संख्या 4 और 7 में से श्रीमती प्रिया जैन) ने हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार 25.04.2016 को विवाह किया और उक्त विवाह में से एक बच्चे (बेटे) का जन्म 06.12.2019 को हुआ। इसके बाद, कुछ वैवाहिक कलह के कारण, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने वर्ष 2020 से एक-दूसरे से अलग रहना शुरू कर दिया, जिसके बाद, वर्ष 2023 में, वैवाहिक विवाद से संबंधित कार्यवाही शुरू की गई

और ऐसी कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता की पत्नी (श्रीमती प्रिया जैन) की सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री राजेश पंवार ने कहा कि याचिकाकर्ता का बेटा अपने नाना-नानी के साथ-साथ मामा (मामा) की अभिरक्षा में है और बेटा 3 साल और 10 महीने का नाबालिग है, और इसलिए, याचिकाकर्ता, पिता होने के नाते, उक्त बच्चे का कानूनी और स्वाभाविक अभिभावक है।

3.1. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता अपने नाबालिग बेटे की अभिरक्षा प्राप्त नहीं कर सका, और इस प्रकार, उसे आशंका है कि उसके बेटे को निजी उत्तरदाताओं द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है, और इसलिए, वर्तमान याचिका विचारणीय है।

3.2. विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे को निजी उत्तरदाताओं द्वारा अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, और यह भी कि यदि कोई अवैध हिरासत है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इस माननीय न्यायालय के समक्ष बनाए रखा जा सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के अनुसार।

3.3. इस तरह के प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 402/2021, 14.07.2022 को निर्णीत); तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य (2019) 7 एससीसी

42; यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 127/2020, 20.01.2020 को निर्णीत) के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश (सुप्रा) में दिए गए फैसले के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"91. इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नाबालिगों के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने में, जिस अधिकार क्षेत्र का न्यायालय प्रयोग करता है, वह एक अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है जो किसी विशेष क़ानून में किसी विशेष प्रावधान द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकार क्षेत्र से अलग है। दूसरे शब्दों में, बाल अभिरक्षा मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का उपयोग किसी भी क़ानून के अनुसार नहीं है, बल्कि उससे स्वतंत्र है। न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता ऐसे मामलों में अपनी अंतर्निहित न्यायसंगत शक्तियों पर टिकी होती है और अपने छोटे वार्ड की सुरक्षा के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है, और जांच की प्रकृति और दायरा और परिणाम को पूरा करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि नाबालिग बच्चों पर लागू होता है, यह निर्धारित करना है कि किसकी अभिरक्षा में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को संभवतः आगे बढ़ाया जाएगा। अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए एक माता-पिता द्वारा दूसरे के खिलाफ लाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, अदालत के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों का सवाल होता है, जैसा कि उनके बीच होता है, और यदि अभिवचनों और साक्ष्यों द्वारा प्रस्तुत

किया जाता है, तो उसके सामने उस हित का सवाल भी होता है जो माता-पिता के संरक्षक के रूप में राज्य को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देने में है।"

तेजस्विनी गौड़ और अन्य में दिए गए निर्णय का प्रासंगिक भाग (सुप्रा) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"19. बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को उचित ठहराने या जांच करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा को न्यायालय के विवेक के अनुसार संबोधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक असाधारण उपाय है और रिट जारी किया जाता है जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में, कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपाय या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है; अन्यथा एक रिट जारी नहीं किया जाएगा। बाल अभिरक्षा मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी नाबालिग को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया जाता है जो अपनी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत मुद्दे पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, बाल अभिरक्षा मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट अनुरक्षणीय है जहां यह साबित होता है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे को हिरासत में रखना अवैध था और कानून के किसी भी अधिकार के बिना था।

20. बाल अभिरक्षा मामलों में, सामान्य उपाय केवल हिंदू

अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम या अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत निहित है, जैसा भी मामला हो। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर अदालत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करती है। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत जांच और एक रिट अदालत द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो प्रकृति में संक्षिप्त है। जो महत्वपूर्ण है वह है बच्चे का कल्याण। रिट अदालत में, अधिकारों का निर्धारण केवल शपथ पत्रों के आधार पर किया जाता है। जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, अदालत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पक्षों को दीवानी अदालत से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है। यह केवल असाधारण मामलों में है, नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

21. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता माँ ज़ेलम की बहनें और भाई हैं जिनके पास नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जबकि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, पहला प्रतिवादी पिता नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक है और उसे बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने का कानूनी अधिकार है। बच्चे की अभिरक्षा के लिए पिता की पात्रता

विवादित नहीं है और डेढ़ साल की उम्र का बच्चा अपनी विवेकपूर्ण प्राथमिकताओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। इसलिए, हमारे विचार में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पिता, स्वाभाविक अभिभावक होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बच्चे की अभिरक्षा की मांग करने वाले असाधारण उपाय का आह्वान करना उचित था।"

4. दूसरी ओर, श्री एम. ए. सिद्दीकी, विद्वान जी.ए. सह ए. ए. जी., प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित श्री रोहित मुथा द्वारा सहायता प्राप्त; निजी प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित सुश्री प्रियंका बोराना की सहायता से वरिष्ठ वकील श्री धीरेंद्र सिंह ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण अनुरक्षणीय नहीं है, और बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित दावे पर निर्णय लेने का भी प्रावधान है, इस प्रकार, वर्तमान याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।

4.1. इसके अलावा, निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि जब हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के तहत उचित और उचित उपाय उपलब्ध है, तो माननीय न्यायालय, सामान्य रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है, विशेष रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय लेते समय।

4.2. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि बच्चा अपनी माँ की दुखद और आकस्मिक मृत्यु के बाद अपने नाना और मामा

के साथ रह रहा है, और वर्तमान में एक स्कूल में कक्षा एल. के. जी. में भर्ती है, इसके अलावा, निजी उत्तरदाता बच्चे को बनाए रखने और उसकी शैक्षणिक और कल्याण की संभावनाओं को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं, और इसलिए, बच्चे को अवैध रूप से हिरासत में रखने का कोई मामला बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, और इसके अभाव में, वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की गई और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. इस न्यायालय ने शुरू में ही यह पाया कि वर्तमान याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और इस पर केवल विचारणीयता के प्रश्न पर ही निर्णय लिया जा रहा है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-पिता अपनी पत्नी की दुखद और अचानक मृत्यु के पश्चात अपने लगभग 4 वर्ष की आयु के नाबालिग पुत्र की अभिरक्षा उसके नाना और मामा से चाहता है।

7. इस न्यायालय ने आगे कहा कि तेजस्विनी गौड़ और अन्य (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल उस मामले में निहित है, जहां कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि "जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, अदालत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पक्षों को दीवानी अदालत का दरवाजा

खटखटाने का निर्देश दे सकती है। यह केवल असाधारण मामलों में है, नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

7.1. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेजस्विनी गौड़ और अन्य (सुप्रा) में दिए गए फैसले का पालन किया और कहा कि "नाबालिग की अभिरक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता के सवाल की इस न्यायालय द्वारा तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य (2019) 7 एस. सी. सी. 42 में जांच की गई थी, और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिका अनुरक्षणीय होगी जहां माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा हिरासत अवैध और कानून के किसी भी अधिकार के बिना पाई जाती है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के विशेषाधिकार रिट के असाधारण उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। यह न्यायालय आगे देखता है कि केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुरक्षणीय माना जाता है; ऐसे मामले में जहां एक नाबालिग बच्चे की अवैध हिरासत काफी हद तक साबित और स्थापित है, तो ऐसा मामला असाधारण श्रेणी के तहत आता है। वर्तमान मामले में, वैवाहिक विवाद के बाद, याचिकाकर्ता की पत्नी अलग रहने लगी, जिसके बाद सड़क दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और तब से नाबालिग बच्चा अपने नाना और मामा (मामा) के साथ रह रहा है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि

नाबालिग बच्चा अवैध हिरासत में है ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सके।

8. यह न्यायालय यह भी देखता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तब तक अनुरक्षणीय नहीं है जब तक कि यह उपरोक्त के रूप में असाधारण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, अन्यथा, कोई भी व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय को समाप्त किए बिना न्यायालय का रुख कर सकता है।

9. इस न्यायालय ने आगे कहा कि आम तौर पर, एक बच्चे की अभिरक्षा के दावे के संबंध में, क़ानून के तहत प्रभावी उपाय प्रदान किया जाता है, जिसमें विस्तृत जांच की जानी है और विशेष रूप से, एक नाबालिग बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना है। वर्तमान मामले में, नाबालिग बच्चा अपने नाना और मामा के साथ रह रहा है और याचिकाकर्ता बच्चे का पिता है, और इसलिए, वर्तमान मामले में एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, और फिर उपचार, जो बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि कारण को कम करेगा, का सहारा लेने की आवश्यकता है, लेकिन समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में, बच्चे के कल्याण और अन्य संभावनाओं के रूप में एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।

10. यह न्यायालय यह भी देखता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उठाया गया मुद्दा हमेशा उस विशेष मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अधीन होगा, और विशेष रूप से, बच्चे की अभिरक्षा से

संबंधित मामलों में, न्यायालय को अभिरक्षा के संबंध में हाल के परिवर्तनों, यदि कोई हों, पर उचित विचार करना होगा, जो ऐसे मामलों में बच्चे के सर्वोपरि कल्याण को निर्धारित कर सकता है। किसी बच्चे की अभिरक्षा में कोई भी तत्काल और हालिया परिवर्तन, जो काफी हद तक उसके कल्याण को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक अच्छा कारण होगा।

11. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बनाए रखते हुए, व्यापक हैं, और भारत के संविधान के अध्याय-III, विशेष रूप से, अनुच्छेद 21 का अर्थ निर्णय को व्यापक आयाम देते हुए लगाया जाना चाहिए।

12. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, किसी भी तरह से, यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता-पिता को हाल ही में अपने नाबालिग बेटे की अभिरक्षा से वंचित किया जा रहा है, बल्कि यह रिकॉर्ड की बात है कि बच्चे के जन्म के बाद वह थोड़े समय के लिए अपने माता-पिता के साथ था, और जब याचिकाकर्ता की पत्नी (मां) ने उससे अलग रहना शुरू किया, तो बच्चा अपनी मां की अभिरक्षा में था; लगभग चार साल तक, याचिकाकर्ता (पिता) की बच्चे के पालन-पोषण में कोई भूमिका नहीं थी, और उसके पालन-पोषण में मातृ गृह की पूरी भूमिका थी। अलग रहने का ऐसा उदाहरण, जैसा कि अभिलेख से पता चलता है, बच्चे के पिता और माँ के बीच गंभीर विवाद के कारण उत्पन्न हुआ।

13. इस न्यायालय का मानना है कि हिरासत के मुद्दे जो लंबे समय से मौजूद हैं, जैसा कि इसमें शामिल है, कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नहीं निपटाए जा सकते हैं। वर्तमान मामले में, माता और पिता के बीच मुकदमेबाजी दोनों पक्षों के बीच पीड़ा और कटुता को दर्शाती है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की अवधि से संबंधित है। इस प्रकार, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता-पिता के पास पिछले चार वर्षों से अपने नाबालिग की अभिरक्षा नहीं है, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में तत्काल निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

14. कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, बच्चे के सर्वोपरि कल्याण का आकलन करने के लिए, कभी-कभी एक व्यापक अर्थ और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है ताकि संबंधित पक्ष अपने दावों को मजबूत तथ्यात्मक और साथ ही कानूनी आधार पर स्थापित कर सकें।

15. चूँकि मामले के समग्र तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि वे असाधारण मामलों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जहाँ कानून के तहत प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो अनुपलब्ध है या अप्रभावी है, वही वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में निर्णय को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।

16. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ उपरोक्त पूर्ववर्ती कानूनों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप

में इसकी स्थिरता के एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में अपने सभी कानूनी मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें बच्चे के सर्वोपरि कल्याण का पहलू भी शामिल है, जिससे सक्षम अदालत द्वारा कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। याचिकाकर्ता के लिए सीमा अवधि वर्तमान आदेश में याचिकाकर्ता को दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तारीख से शुरू होगी। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे (डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।